



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 12 सितम्बर, 2019 / 21 भाद्रपद, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 4 सितम्बर, 2019

संख्या: पीसीएच-एचए(1)6/2014-52775-913.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के साथ पठित धारा 135 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने

के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इनका जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में एतद्वारा प्रकाशन किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले यदि किसी व्यक्ति को उक्त नियमों को बनाए जाने की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे /उन्हें प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एसडीए कम्प्लैक्स, ब्लॉक नं० 27, कसुम्पटी, शिमला-171 009 को भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) यदि कोई हो (हों) पर राज्य सरकार द्वारा इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात:-

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में कनिष्ठ लेखाकार की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2019 है।

2. परिभाषाएं.—1 इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) अधिनियम से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है; और

(ख) श्रृंखला से, इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।

3. पदों की संख्या.—प्रत्येक जिला परिषद् में कनिष्ठ लेखाकार के पदों की संख्या ऐसी होगी, जैसी सरकार द्वारा मंजूर की गई है और जैसी समय-समय पर मंजूर की जाए।

4. वेतनमान.—कनिष्ठ लेखाकार के पद के लिए वेतनमान निम्न प्रकार से होगा;

(क) नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए पे बैंड मु० 5910-20200+1900 ग्रेड पे

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां नियम 13 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार मु० 5910+1900+7810/- प्रतिमास; और

(ग) कनिष्ठ लेखाकार को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए सहायता अनुदान में से मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा।

5. पद का प्रकार (चयन या अचयन पद).—कनिष्ठ लेखाकार का पद अचयन होगा

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—कनिष्ठ लेखाकार के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा यदि वह 18 से 45 वर्ष की आयु का हो:

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और कि समस्त पब्लिक सेक्टर नियमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे नियमों /स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालायों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, राज्य सरकार के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं.—1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से कम से कम पचास प्रतिशत अंकों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में पैतालीस प्रतिशत अंकों) सहित वाणिज्य या कला में (अर्थशास्त्र या गणित या लेखांकन के एक विषय सहित) स्नातक की उपाधि।

2. उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता रखते हों।

8. परिवीक्षा की अवधि.—नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी एक वर्ष से अनधिक किसी और अवधि के विस्तारण के अध्यधीन, जैसा जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष परिस्थितियों में कारणों के लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

9. नियुक्ति की पद्धति.—अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

10. सीधी/संविदा नियुक्ति के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—कनिष्ठ लेखाकार के रूप में नियुक्त किया जाने वाला अभ्यर्थी हि0 प्र0 का स्थाई निवासी होना चाहिए।

11. नियुक्ति के लिए चयन.—यथास्थिति, सीधी या संविदात्मक नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियम 13(पअ) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

12. नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए सेवा की शर्तें.—संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण राज्य सरकार के संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति के अनुसार किया जाएगा। जिला परिषद् काडर के अधीन नियमित किया गया कनिष्ठ लेखाकार अधिसूचना तारीख 27 सितम्बर, 2017 द्वारा यथाअधिसूचित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की सुविधा प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में सेवा की अन्य शर्तें यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे लागू होंगी जैसी राज्य सरकार के कनिष्ठ लेखाकारों की दशा में लागू हैं।

13. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए

भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:—

(i) संकल्पना:

(क) इन नियमों के अधीन जिला परिषद् में कनिष्ठ लेखाकार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल निदेशक, पंचायती राज का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना:

सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को भेजेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) संविदात्मक उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को 7810/—रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 235/—रु0 की रकम पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:

सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) चयन प्रक्रिया:

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(v) नियुक्ति और करार:

चयन के पश्चात् अभ्यर्थी को प्ररूप-८ में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उसे इन नियमों से संलग्न प्ररूप-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vi) निबन्धन और शर्तें:

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/— रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति

आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में वृद्धि अर्थात् पद के पे-बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं किया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूती अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुभयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से, स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्त के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानांतरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति परिसंकटमय प्रकृति की ड्यूटी के विरुद्ध की जाती है और यदि उन्हें सेवा शर्त के रूप में प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण करनी होगी तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परिक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0 एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

14. नियुक्ति प्राधिकारी.—(1) सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और नियुक्ति-पत्र जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) सम्बद्ध जिला परिषद् का सचिव प्रवास (दौरे) कार्यक्रम, छुट्टी आदि के लिए नियंत्रण अधिकारी होगा।

15. कनिष्ठ लेखापाल की वरिष्ठता.—नियमित कनिष्ठ लेखाकार की वरिष्ठता भर्ती अभिकरण द्वारा विरचित मैरिट सूची (गुणागुण) के अनुसार अवधारित की जाएगी या स्कीम के अधीन नियुक्त पूर्वतर कनिष्ठ लेखाकारों के मामले में कार्यग्रहण की तारीख से अवधारित की जाएगी और निदेशालय स्तर पर समेकित तथा अनुरक्षित की जाएगी।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. जॉब चार्ट.—कनिष्ठ लेखाकार के लिए जॉब चार्ट ऐसा होगा, जैसा समय-समय पर जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

18. प्रशिक्षण और परीक्षा.—सेवा के सदस्यों को परीक्षा उर्तीण करनी होगी या प्रशिक्षण के लिए ऐसे कोर्स करने होंगे, जैसे जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परन्तु उसे ऐसी परीक्षा को अर्हित करने के लिए पांच वर्ष में तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे और सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा परीक्षा अर्हित न करने की दशा में, ऐसा कर्मचारी पदच्युत किए जाने के लिए दायी होगा।

19. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को, किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

20. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को और पंचायत समितियों द्वारा अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0—एच0बी0 (1) 43/01, तारीख 20 अगस्त, 2001 द्वारा संविदा के आधार पर कनिष्ठ लेखाकार को नियुक्त करने के लिए अधिसूचित स्कीम निरसित हो जाएगी।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

प्ररूप—I

खनियम 13 (5) देखें,
नियुक्ति पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री, श्री..... निवासी
गाँव.....तहसील.....जिला..... से कनिष्ठ लेखाकार के पद के लिए प्राप्त
आवेदन के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी..... को उक्त पद

के लिए चयनित किया गया है। इसलिए, अतः उसे निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर कनिष्ठ लेखाकार के रूप में नियुक्ति प्रस्तावित की जाती है:—

1. उसे प्रतिमास रुपए (अंको में) (अक्षरों में) पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा;
2. कोई अन्य भत्ता, जैसा भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय है, उसे संदत्त नहीं किया जाएगा;
3. प्रारम्भ में नियुक्ति, संविदा आधार पर, कार्यग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे नियमों के उपबन्धों के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा;
4. इसके अतिरिक्त नियुक्ति, नियमों और करार में अधिकथित निबन्धनों और शर्तों के भी अध्यक्षीन होगी;
5. कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, उसके द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पिछले कम से कम तीन वर्ष से उसे जानने वाले दो राजपत्रित अधिकारियों से, अधोहस्ताक्षरी के समाधान के लिए, पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण-पत्र दिया जाएगा;
6. नियुक्ति, पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व, सम्बद्ध जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता (स्वस्थता) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगी; और
7. यथास्थिति, शैक्षिक अर्हताओं, जाति, स्थायी निवासी, शारीरिक अक्षमता, गरीबी रेखा से नीचे से संबन्धित सदस्य या पूर्व अनुभव की बाबत, मूल प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

यदि उसे, उपरोक्त निबन्धन और शर्तें स्वीकार्य हैं, तो वह, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में तुरन्त, किन्तु इस नियुक्ति पत्र के जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अपश्चात्, संविदा करार के निष्पादन के साथ-साथ कार्यग्रहण के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी।

स्थान
तारीख.....

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्
जिला.....
हिमाचल प्रदेश।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....

प्ररूप-II खनियम 13 (5) देखें,

करार

कनिष्ठ लेखाकार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्..... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के मध्य निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और जिला परिषद् के मध्य इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने संविदा के आधार पर कनिष्ठ लेखाकार के रूप में निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह की प्रथम पक्षकार कनिष्ठ लेखाकार के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार को संविदात्मक रकम 7810/— रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिनके चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के अनधिक प्रसूति अवकाश (जिवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा;

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामलों में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा;

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हों।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपना आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति परिसंकटमय प्रकृति की ड्यूटी के विरुद्ध की जाती है और यदि उन्हें सेवा शर्त के रूप में प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण करनी होगी तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख के छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के संबन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास व वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1. (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.
.....
..... (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव (पंचायती राज)।

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171 009, the 4 September, 2019*

NO. PCH-HA-(1) 6/2014-52775-913.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 135 read with Section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994(Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules for carrying out the purposes of the Act *ibid* and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestions(s) to make with regard to the said rules, he may send the same to the Director of Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Block No. 27, Kasumpti, Shimla-171009, within a period of thirty days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objections(s) or suggestions(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these rules, namely:—

DRAFT RULES

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Junior Accountant in Zila Parishads) Rules, 2019.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994; and
- (b) “Form” means a form appended to these rules.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Number of posts.—There shall be such number of posts of Junior Accountant as sanctioned and may be sanctioned by the State Government from time to time in the respective Zila Parishads.

4. Scale of Pay.—The scale of pay for the post of Junior Accountant shall be as under:—

- (a) Pay band for regular appointees: PB-Rs. 5910—20200 + 1900 Grade Pay.
- (b) Emoluments for contractual appointees: Rs. 5910+1900=7810/- per month as per details given in rule 13; and
- (c) The monthly remuneration shall be provided to the Junior Accountant out of the Grant-in-Aid provided by the State Government.

5. Type of post (whether selection or non Selection post).—The post of the Junior Accountant shall be non-selection.

6. Age for direct appointment.—A person to be appointed as Junior Accountant shall be eligible if he is having the age between 18 and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad-hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad-hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad-hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Categories of persons to the extent permissible under the General or Special Order (s) of the State Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience, in the case of direct appointment, are relaxable at the discretion of the State Government in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational qualifications required for direct appointment.—(1) Bachelor's Degree in Commerce or Arts with (Economics or Maths or Accounting as one of the subjects) with not less than 50% marks. (45% marks in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes) from Himachal Pradesh University or any other institute recognized by the Himachal Pradesh Government.

(2) Preference shall be given to those candidates who have knowledge of customs, manners and dialect of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8. Period of Probation.—The regular appointee shall remain under probation for a period of two years subject to such further extension for a period of not exceeding one year, as may be ordered by the Chief Executive Officer of Zila Parishad in special circumstances and reasons thereof to be recorded in writing.

9. Method of appointment.—The candidate shall be appointed by direct recruitment either on regular basis or on contract basis, as the case may be.

10. Essential requirement for direct/contract appointment.—The candidate to be appointed as Junior Accountant must be a bonafide resident of Himachal Pradesh.

11. Selection for appointment.—The selection to the post, in case of direct or contractual appointment, as the case may be, shall be made by the Selection Committee as per details given in Rule 13 (IV).

12. Conditions of Service for regular appointees.—The regularization of the contract employees shall be made in accordance with the policy of regularization of the contract employees of the State Government. The Junior Accountant so regularized under the Zila Parishad Cadre shall be entitled for availing the facility of National Pension Scheme (NPS) as has been notified *vide* notification dated 27th September, 2017. The other conditions of service in the case of regular appointees shall apply *mutatis-mutandis* as are applicable in case of State Government Junior Accountants.

13. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under these rules the Junior Accountant in Zila Parishad will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned Chief Executive Officer shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract will be renewed/ extended after taking prior approval of the Director, Panchayati Raj.

(b) Post Falls Within The Purview of The Himachal Pradesh Staff Selection Commission : The Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis shall send requisition to the Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(c) The Selection will be made in accordance with eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Junior Accountant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 7810/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+ Grade pay). An amount of Rs. 235/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post, in case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient by a interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(V) APPOINTMENT AND AGREEMENT:

After selection of a candidate, an appointment letter will be issued to him in Form-I and he/she shall sign an agreement as per Form-II appended to these rules.

(VI) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ 7810/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay in pay band+ grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount *i.e.* 3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post for further extended year(s) and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee :

Provided that un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Chief Executive Officer, Zila Parishad shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on administrative grounds.

(f) The selected candidate, in case of a gazetted Government Servant, by the medical board and in the case of non-gazetted Government servant by the Government medical Officer, must submit a certificate of his/her fitness. In case of women candidates, who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duty and if they have to complete the term of the training as condition of service, such female candidates, who found to be pregnant for 12 weeks or more will stand temporarily unfit and his appointment will be deferred till the end of confinement. Such women candidates will be re-examined for medical suitability after six weeks from the date of confinement and if it is found suitable by submission of fitness certificate from the above mentioned authority, then it shall be appointed for the post reserved for it.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR/SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled to the emoluments as defined in this column.

14. Appointing Authority.—(1) The Chief Executive Officer of concerned Zila Prishad shall be the appointing authority and letter of appointment shall be issued by the Chief Executive Officer, Zila Parishad.

(2) The Secretary of the concerned Zila Parishad shall be the controlling officer for tour programme, leave etc.

15. Seniority of Junior Accountant.—The seniority of the regular Junior Accountant shall be determined as the merit list formulated by the recruiting agency or in case of the Junior Accountants earlier appointed under the Scheme shall be determined from the date of joining and consolidated and maintained at Directorate level.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Job Chart.—The job chart for the Junior Accountant shall be such as may be specified by the Chief Executive Officer of Zila Parishad from time to time.

18. Training and Examination.—The members of the service shall have to qualify examination or to undergo such courses for training as may be specified by the Chief Executive Officer of Zila Parishad with the approval of the Government, from time to time:

Provided that three chances shall be provided to qualify such examination within five years and in the event of not qualifying the examination by the concerned employee, the services of such employee shall be liable to be terminated.

19. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions(s) of these rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).

20. Repeal and Savings.—(1) On and from the date of commencement of these rules, the Scheme notified for the appointment of Junior Accountant on contract basis by Panchayat Samitis *vide* notification No. PCH-HB (1) 43/01, dated 20th August, 2001 shall stand repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken, under the scheme so repealed, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

FORM-1

[See rule 13(V)]

APPOINTMENT LETTER

With reference to the application for the post of Junior Accountant received from Shri/Smt./Kumari.....son/wife/daughter of Shri

....., resident of village, Tehsil, district it is informed that the said Shri/Smt./Kumari has been selected for the said post. Therefore, he/she is hereby offered appointment as Junior Accountant on the following terms and conditions:—

1. that there shall be paid to him/her a remuneration of rupees (in figures) (in words) per month;
2. that no other allowance, whatsoever admissible to the employees of State Government from time to time shall be paid to him/her;
3. that the appointment shall be on contract basis initially for a period of one year from the date of joining which may be extended as per the provisions of the rules;
4. that the appointment further shall be subject to terms and conditions laid down in the rules and agreement ;
5. that the antecedent verification certificate to the satisfaction of the Zila Parishad from the Executive Magistrate or two Gazetted officers known to him at least for the last three years shall be given by him/her at the time of submission of joining report;
6. that the appointment shall be subject to the production of Certificate of Medical Fitness issued by the Chief Medical Officer of the concerned district before joining to the post; and
7. that the attested copies of original certificates in respect of educational qualifications, caste, bonafide resident, physically handicapped, member belonging to below poverty line or past experience, as the case may be, shall be submitted along with joining report.

In case, the above terms and conditions are acceptable to him/her, he/she may report for execution of the contract agreement as well as for joining duty in the office of undersigned immediately but not later than fifteen days from the date of issue of this appointment letter.

Place :

Chief Executive Officer,
Zila Parishad _____
District _____
Himachal Pradesh.

Date :

Shri/Smt./Kr. _____

FORM-2

[See rule 13(V)]

AGREEMENT

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Accountant and the Chief Executive Officer, Zila Parishad _____ (Designation of the Appointing Authority)

This agreement is made on this _____ day of _____
in the year _____ Between Sh./Smt. _____ s/o/d/o/w/o
Shri _____ r/o _____

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Zila Parishad _____ through its Chief Executive Officer (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Accountant on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Accountant for a period of 1 (one) year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the Chief Executive Officer shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 7810/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee;

Provided that un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. The selected candidate, in case of a gazetted Government Servant, by the medical board and in the case of non-gazetted Government servant by the Government medical Officer, must submit a certificate of his/her fitness. In case of women candidates, who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duty and if they have to complete the term of the training as condition of service, such female candidates, who found to be pregnant for 12 weeks or more will stand temporarily unfit and his appointment will be deferred till the end of confinement. Such women candidates will be re-examined for medical suitability after six weeks from the date of confinement and if it is found suitable by submission of fitness certificate from the above mentioned authority, then it shall be appointed for the post reserved for it.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Signature of the SECOND PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

By order,
Sd/-

Secretary (Panchayati Raj).

OFFICE OF MUNICIPAL COUNCIL BADDI, DISTRICT SOLAN (H.P.)

NOTIFICATION

Baddi-173205, the 5th September, 2019

No. MCBaddi/SLB/2019-2280.—In order to comply with the order of Director, Urban Development Shimla *vide* letter No. UD-(C)(10)-1//2016-1-21089-92 dated 18-07-2019, in this regard for release of general and performance grant. The Municipal Council Baddi, District Solan (H.P.) is

pleased to notify the Service Level Benchmark for four services sectors *i.e.* Water Supply, Sewerage, Storm Water Drainage and Solid Waste Management which are proposed to be achieved by the Municipal Council Baddi before 31-03-2020.

Service Level Benchmarks for Performance Grant of 2019-20

| Sl. No. | Indicators | MoHUA Benchmark | Status 2018-19 | Target 2019-20 |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Water Supply Services | | | | |
| 1. | Coverage of water supply connections | 100% | 86 | 86 |
| 2. | Per capita supply of water | 135 lpcd | 70 | 70 |
| 3. | Extent of metering of water connections | 100% | 65 | 66 |
| 4. | Extent of Non-Revenue Water (NRW) | 20% | 33 | 32 |
| 5. | Continuity of water supply | 24 hours | 8 | 8 |
| 6. | Quality of water supplied | 100% | 100 | 100 |
| 7. | Efficiency in redressal of customer complaints | 80% | 75 | 75 |
| 8. | Cost recovery in water supply services | 100% | 25 | 30 |
| 9. | Efficiency in collection of water supply related charges. | 90% | 80 | 82 |
| Sewage management (Sewerage and Sanitation) | | | | |
| 1. | Coverage of toilets | 100% | 100 | 100 |
| 2. | Coverage of sewage network services | 100% | 97 | 97 |
| 3. | Collection efficiency of the sewage network | 100% | | |
| 4. | Adequacy of sewage treatment capacity | 100% | | |
| 5. | Quality of sewage treatment | 100% | | |
| 6. | Extent of reuse and recycling of sewage | 20% | | |
| 7. | Efficiency in redressal of customer complaints | 80% | 75 | 75 |
| 8. | Extent of cost recovery in sewage management | 100% | | |
| 9. | Efficiency in collection of sewerage charges | 90% | | |
| Solid Waste Management | | | | |
| 1. | Household level coverage of Solid Waste Management services. | 100% | 80 | 100 |
| 2. | Efficiency of collection of municipal solid waste | 100% | 76 | 77 |
| 3. | Extent of segregation of municipal solid waste | 100% | 35 | 60 |
| 4. | Extent of municipal solid waste recovered | 80% | 18 | 40 |
| 5. | Extent of scientific disposal of municipal solid waste | 100% | 75 | 75 |
| 6. | Efficiency in redressal of customer complaints | 80% | 80 | 80 |
| 7. | Extent of cost recovery in SWM services | 100% | 10 | 10 |
| 8. | Efficiency in collection of SWM charges | 90% | 10 | 10 |
| Storm Waster Drainage | | | | |
| 1. | Coverage of Storm water drainage network | 100% | 40 | 45 |
| 2. | Incidence of water logging/flooding | 0% | 0 | 0 |

SLB Status of 2018-19

| | | | |
|----|---|------|-----|
| 1. | Coverage of Water Supply (24 X 7) in all Public/Community Toilets | 24X7 | YES |
| 2. | Percentage of waste being processed scientifically* | 100% | 30 |

Sd/-
Executive Officer,
Municipal Council Baddi,
District Solan (H.P.).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-61/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसमें इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

| क्र० सं० | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हेक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
|----------|--------------|---|-------------|------------|------------------------|--|---------------|----------|-------|
| 1. | 10/2015 | भोग-द्वितीय | भोग | 684 | 10-26-33 | उत्तर:-भोग दक्षिण:-भोग पूर्व:-भोग पश्चिम:-भोग | मशोबरा | शिमला | शिमला |

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-61/2019, dated 31st July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-61/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the

SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
|---------|----------|---|---------------|-------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|----------|
| 1. | 10/2015 | Bhog-II | Bhog | 684 | 10-26-33 | North:-Bhog South:-Bhog East:-Bhog Wes:-Bhog | Mashobra | Shimla | Shimla |

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-62/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

| क्र० सं० | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
|----------|--------------|---|-------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------|----------|------|
|----------|--------------|---|-------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------|----------|------|

| | | | | | | | | | |
|----|---------|------|------|--|----------|---|--------|-------|-------|
| 1. | 11/2015 | कुफर | कुफर | 1, 53, 101, 102, 209 कित्ता ..5 | 29-19-46 | उत्तर:-कुफर व भवाणा दक्षिण:-कुफर एवं डी.पी.एफ. भवाणा पूर्व:-कुफर पश्चिम:-डी.पी.एफ. भवाणा | मशोबरा | शिमला | शिमला |
|----|---------|------|------|--|----------|---|--------|-------|-------|

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-62/2019, dated 31st July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-62/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number(s) | Area in hectare(s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
|---------|----------|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------|-----------------|----------|
| 1. | 11/2015 | Kufar | Kufar | 1, 53, 101, 102, 209 Kitta ..5 | 29-19-46 | North:- Kufar & Bhawana South:- Kufer, DPF Bhwana East:- Kufar West:- DPF Bhwana | Mashobra | Shimla | Shimla |

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-63/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

| क्र० सं० | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
|----------|--------------|---|-------------|---------------------------|------------------------|---|---------------|----------|-------|
| 1. | 12/2015 | बड़ाह-द्वितीय | बड़ाह | 31, 310/1 किता.. 2 | 9-38-77 | उत्तर:-ढली-द्वितीय दक्षिण:-बड़ाह पूर्व:-बड़ाह पश्चिम:-ढली-द्वितीय, बड़ाह | मशोबरा | शिमला | शिमला |

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-63/2019, dated 31st July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-63/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the

SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
|---------|----------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|----------|
| 1. | 12/2015 | Badah-II | Badah | 31, 310/1 Kitta.. 2 | 9-38-77 | North:- Dhalli-II South:- Badah East:- Badah West:- Dhalli-II, Badah | Mashobra | Shimla | Shimla |

By order,

RAM SUBHAG SINGH.
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-64 / 2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

| क्र० सं० | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
|----------|--------------|---|-------------|----------------------------------|------------------------|--|---------------|----------|-------|
| 1. | 13/2015 | मूंगर-प्रथम | मूंगर | 227, 446/2, 483, 485 किता.. 4 | 10-13-71 | उत्तर:-मूंगर दक्षिण:-मूंगर पूर्व:-मूंगर पश्चिम:-मूंगर | मशोबरा | शिमला | शिमला |

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-64/2019, dated 31st July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-64/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
|---------|----------|---|---------------|-----------------------------------|---------------------|--|--------------|-----------------|----------|
| 1. | 13/2015 | Moongar-I | Moongar | 227, 446/2, 483, 485 Kitta ..4 | 10-13-71 | North:-Moongar South:-Moongar East:-Moongar West:-Moongar | Mashobra | Shimla | Shimla |

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-65/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

| क्र० सं० | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | महाल का नाम | खसरा नम्बर | हैक्टेयर में क्षेत्रफल | मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला |
|----------|--------------|---|-------------|---|------------------------|--|---------------|----------|-------|
| 1 | 14/2015 | मेवग-द्वितीय | मेवग | 52, 291, 498, 620, 632, 633 किता.. 6 | 39-89-09 | उत्तर:-मेवग दक्षिण:-चमयाणा पूर्व:-मेवग पश्चिम:-मेवग, शुराला | मशोबरा | शिमला | शिमला |

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F-(14)-65/2019, dated 31st July, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st July, 2019

No. FFE-B-F-(14)-65/2019.—WHEREAS the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of

the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

| Sl. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal | Khasra number (s) | Area in hectare (s) | Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal | Forest Range | Forest Division | District |
|---------|----------|---|---------------|--|---------------------|--|--------------|-----------------|----------|
| 1. | 14/2015 | Mewag-II | Mewag | 52, 291, 498, 620, 632, 633, Kitta ..6 | 39-89-09 | North:- Mewag South:- Chamyana East:- Mewag West:- Mewag, Shurala | Mashobra | Shimla | Shimla |

By order,

RAM SUBHAG SINGH ,
Additional Chief Secretary (Forests).

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक शिमला-2

संख्या:आई0पी0एच0-बी(ए)3-3/2018-I.—राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू. पी. नम्बर: 1537/2018 में पारित तारिख 30-07-2018 के अधिनिर्णय के अनुसरण में और हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण की सिफारिशों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा(3) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को भूगर्भ जल स्रोतों को विनियमित करने, नियन्त्रण करने और उनका वैज्ञानिक रूप से तथा अविरत रीति में प्रबन्धन करने के लिए घोषित/अधिसूचित करने का विनिश्चय किया है;

2. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन भूगर्भ जल के दोहन का नियन्त्रण/विनियमन करने के लिए अधिसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का प्रस्ताव करते हैं और इसे जन साधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

3. उपरोक्त अधिसूचना द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी/किन्ही व्यक्ति(यों) के यदि कोई आक्षेप या सुझाव हो तो वह/वे उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारिख से 30 दिन की अवधि के भीतर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश को लिखित में भेज सकेगा/सकेंगे;

उपरोक्त निमत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हो, पर राज्य सरकार द्वारा अंतिम अधिसूचना को जारी करने से पूर्व विचार किया जाएगा।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
सचिव (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य)।

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA**NOTIFICATION***Shimla-4, the 28th August, 2019*

No.VS-Legn.-Rules Comm./1-30/2014.—The Rules Committee in its Second Report (Thirteenth Vidhan Sabha) 2019- 20, recommended certain amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973. The Report was laid on the table of the House on 20-08-2019. Within seven days, no notice of amendment under rule 261(3) was received. Thus in accordance with the provisions of Rule 261(3), these recommendations are deemed to have been approved by the House. Consequently, the Hon'ble Speaker is pleased to order that these amendments be incorporated in the Rules as per annexure 'A' appended to this notification.

Sd/-
(YASH PAUL SHARMA)
Secretary,
H. P. Vidhan Sabha.

अध्याय—18

| क्रम सं० | नियम संख्या | नियम का टैक्सट |
|----------|-------------------------|---|
| 1. | 272 (ज) समिति का गठन | अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित एक ई—गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति होगी जिसमें 7 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। |
| 2. | 272 (झ) समिति के कृत्य | सभा ई—गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजनों संबंधी विषयों पर सुझाव देना व विचार करना। |
| 3. | 272 (ञ) समिति की बैठकें | जब भी आवश्यकता होगी समिति की बैठकें सभापति बुलाएंगे तथा अध्यक्ष की पूर्वानुमति से समिति विशेषज्ञों एवं अन्य व्यक्तियों को भी बैठक में राय जानने हेतु बुला सकती है। |
| 4. | 272 (ट) अन्य प्रावधान | अन्य बातों के लिए सामान्य नियम जोकि सभा की समिति के अध्याय—18, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य—संचालन नियम में निहित है, वही रहेंगे या संशोधनों के साथ जो अध्यक्ष आवश्यक तथा नियमानुसार सही समझें, लागू होंगे। |

अध्याय—24

| क्रम सं० | नियम संख्या | नियम का टैक्सट |
|----------|--------------|---|
| 1. | नियम 328 (4) | सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं (Notices) पर उनके द्वारा की गई चर्चा की कार्यवाही के चिन्हित भाग का Video Clipping Link उनके मोबाईल ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। |

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सांगला, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर, हि0 प्र0**

मुकद्दमा नम्बर :
06/2019

तारीख संस्थापना
19-08-2018

श्री माया भगत पुत्र जारवी नन्द, निवासी गांव छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Maya Bhagat Negi ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री Miss Aarzo Negi का जन्म दिनांक 03-12-1994 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः आम जनता ग्राम पंचायत छितकुल, तहसील सांगला, जिला किन्नौर को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Maya Bhagat Negi की पुत्री Miss Aarzo Negi का जन्म दिनांक 03-12-1994 का पंजीकरण ग्राम पंचायत छितकुल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 03-10-2019 या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत छितकुल को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 02-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी सांगला,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Hem Raj

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Hem Raj s/o Sh. Jaiu Ram, resident of Village Padova, P.O. Khanag, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an

affidavit stating that the birth event of his daughter Miss Shivani d/o Hem Raj born on 31-07-2016 has not been entered in the record of Gram Panchayat Khanag.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering birth event of daughter of the applicant born on 31-07-2016 in the Panchayat record of Gram Panchayat Khanag, he/she/they may file his /her/their objections on or before 25-09-2019 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 29th day of August, 2019.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Tikam Ram

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Tikam Ram s/o Sh. Manglu Ram, resident of Village Patarna, P.O. Kandugad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the death event of his mother Smt. Parvati Devi w/o Sh. Manglu Ram died on 15-03-2013 has not been entered in the record of Gram Panchayat Karad.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering death event of mother of the applicant died on 15-03-2013, in the Panchayat record of Gram Panchayat Karad, he/she/they may file his /her/their objections on or before 25-9-2019 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 29th day of August, 2019.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.

In the Court of Sh. Amit Guleria (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Sh. Vikram Sharma aged 40 years s/o Sh. Vasudev Sharma, r/o House No. 168, near Kali Sarak, Mohan Nagar Ludhiana, Distt. Ludhiana, Punjab at present residing Shop No. 9, Ward No.

5, Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H. P. and Shaili Sharma aged 37 years d/o Sh. Devender Nath Sharma, r/o Shop No. 9, Ward No. 5, Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H. P.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Vikram Sharma aged 40 years s/o Sh. Vasudev Sharma, r/o House No. 168, near Kali Sarak, Mohan Nagar Ludhiana, Distt. Ludhiana, Punjab at present residing Shop No. 9, Ward No. 5, Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H. P. and Shaili Sharma aged 37 years d/o Sh. Devender Nath Sharma, r/o Shop No. 9, Ward No. 5, Manu Market Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H. P. has presented an application on 29-08-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 29-09-2019 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 2nd day of September, 2019.

Seal.

Sd/-

*Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).*

**In the Court of Sh. Amit Guleria (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Tashi Ram s/o Sh. Chhering, r/o Village Koshla, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and

Smt. Pema Dolma d/o Sh. Dawa, r/o V.P.O. Bahang, Tehsil Manali, District Kullu, H. P. do hereby declare as follows:—

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Tashi Ram s/o Sh. Chhering, r/o Village Koshla, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Smt. Pema Dolma d/o Sh. Dawa, r/o V.P.O. Bahang, Tehsil Manali, District Kullu, H. P. has presented an application on 29-08-2019 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 29-09-2019 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 2nd day of September, 2019.

Seal.

Sd/-

*Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).*

**In the Court of Sh. Vivek Sharma, H.A.S., Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District
Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Shri Raman s/o Shri Mohan Lal, r/o H. No. 165, Street No. 3, near Bus Stand Chhachhroli, District Yamunanagar (HR), c/o Manish Kumar s/o Sh. Darshan Lal, r/o H.No. 305/11 Katcha Tank Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Santosh d/o Sh. Jai Pal, r/o H. N0. 148 Govindpura, District Yamunanagar (HR) have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 26-06-2019 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Raman s/o Shri Mohan Lal, r/o H. No. 165, Street No. 3, near Bus Stand Chhachhroli, District Yamunanagar (HR), c/o Manish Kumar s/o Sh. Darshan Lal, r/o H.No. 305/11 Katcha Tank Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Santosh d/o Sh. Jai Pal, r/o H. N0. 148 Govindpura, District Yamunanagar (HR) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 20th day of August, 2019.

Seal.

VIVEK SHARMA (HAS),
Marriage Officer (S.D.M.), Nahan,
District Sirmaur (H.P.).

